

दि कर्मिक पोस्ट

Email- thekaarmiicpost@gmail.com

Global
School Of
Excellence,
Obedullaganj

वर्ष : 11, अंक : 18

(प्रति बुधवार),

इन्दौर, 3 दिसंबर 2025 से 9 दिसंबर 2025

पेज : 8

कीमत : 3 रुपये

समुद्र से दूर जा रहे दुनिया के 56 फीसदी तटीय क्षेत्र, जलवायु संकट की आहट



तमिलनाडू सदियों से तटवर्ती शहर व्यापार, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के बड़े केंद्र रहे हैं। यही वजह है कि आज भी दुनिया की करीब 40 फीसदी आबादी समुद्र के 100 किलोमीटर के दायरे में रहती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, कटाव, बाढ़ और चक्रवातों जैसी आपदाओं का खतरा बढ़ गया है।

इन बढ़ते खतरों ने तटवर्ती शहरों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। इस बारे में किए गए एक नए वैश्विक अध्ययन से पता चला है कि पिछले तीन दशकों में धरती के आधे से अधिक तटीय बस्तियों ने समुद्र से दूरी बढ़ाई है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे मानो इंसान दबे पांव बढ़ते जलवायु खतरों से बचने की राह खोज रहा हो। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले दशकों में जलवायु संकट बढ़ा है और उसका असर अब तटीय इलाकों में साफ तौर पर दिखने लगा है। यह अध्ययन सिचुआन विश्वविद्यालय से जुड़े शोधकर्ताओं के नेतृत्व में एक अंतरराष्ट्रीय दल द्वारा किया गया है। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन के विशेषज्ञ भी शामिल थे। अपने इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 155 देशों के 1,071 तटीय इलाकों में बस्ती के फैलाव और बदलाव का नक्शा तैयार किया है। यह बदलाव सैटलाइट की मदद से रात की रोशनी (नाइटलाइट) के एकत्र किए गए डेटा के आधार पर दर्ज किया गया है। इस डेटा को वैश्विक स्तर पर सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों के साथ जोड़कर शोधकर्ताओं ने पाया है कि 1992 से 2019 के बीच दुनिया के 56 फीसदी तटीय इलाके समुद्र से दूर खिसक गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि जहां दुनिया का बड़ा हिस्सा समुद्र से दूर जा रहा है, वहीं कुछ इलाके जैसे डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन समुद्र के और भी करीब आ गए हैं। आंकड़ों से पता चला है कि करीब 16 फीसदी तटीय क्षेत्र समुद्र के और करीब आए हैं। दूसरी तरफ 28 फीसदी इलाकों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। शोधकर्ताओं के मुताबिक तटीय इलाकों के समुद्र से दूर हटने को अनुकूलन की एक रणनीति माना जाता है। लेकिन इतना बड़ा बदलाव क्यों और कहां हो रहा है, इसके पीछे का असली कारण स्पष्ट नहीं था। जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित इस अध्ययन में पहली बार वैश्विक स्तर पर यह साबित हुआ है कि तटीय इलाकों के पीछे हटने का बड़ा कारण प्राकृतिक आपदाएं नहीं, बल्कि सामाजिक कमजोरियां और

कमजोर बुनियादी ढांचे हैं। स्टडी में सामने आया है कि यह बदलाव अफ्रीका और ओशिनिया में कहीं ज्यादा स्पष्ट है। अफ्रीका में जहां 67 फीसदी तटीय इलाके समुद्रों से दूर जा रहे हैं। वहीं ओशिनिया के 59 फीसदी तटीय क्षेत्रों में पीछे हटने की प्रवृत्ति देखी गई है।

हालांकि दूसरी ओर एशिया और दक्षिण अमेरिका के कई इलाकों में तटीय विस्तार जारी है, यानी लोग जोखिम के बावजूद समुद्र की ओर बढ़ रहे हैं। अध्ययन में इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि दुनिया के कई कमजोर तटीय इलाकों, खासकर अफ्रीका और एशिया में, अब भी लोग समुद्र से दूर नहीं जा पा रहे। गरीबी, संसाधनों की कमी, आजीविका के सीमित विकल्प, तटीय जमीन पर निर्भरता इसकी बड़ी वजहें हैं। इनकी वजह से कई कमजोर समुदाय जोखिम के बावजूद तटों पर ही रहते हैं। नतीजन वे तटीय बाढ़ और कटाव जैसी जलवायु आपदाओं के प्रति और अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

अमीर देशों में समुद्र के करीब बसने की प्रवृत्ति

दिलचस्प बात यह है कि समुद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा मझोले आय वाले देशों में दिखती है। शोधकर्ताओं के अनुसार ये देश एक अहम मोड़ पर खड़े हैं। यह देश न तो इतने गरीब हैं कि कुछ न कर सकें, और न इतने अमीर कि पूरी तरह सुरक्षित बुनियादी ढांचा विकसित कर सकें।

लागोस शहर; फोटो: आईस्टॉक

हालांकि इनके पास सुरक्षित जगहों पर बसाने के लिए क्षमता और धन तो है। इसलिए इन देशों में योजनाबद्ध तरीके से तटों से दूर जाना अधिक दिखता है। देखा जाए तो कमजोर और बहुत अधिक आय वाले दोनों तरह के क्षेत्र समुद्र के पास ही बने रहते हैं या और भी करीब जाते हैं, लेकिन उनकी वजहें बिल्कुल अलग-अलग हैं। कमजोर इलाकों में लोग रोजगार, बुनियादी सुविधाओं और आर्थिक अवसरों की तलाश में तट के पास ही बसे रहते हैं।

इसके विपरीत, अमीर देश अपनी मजबूत संरचनाओं, शुरुआती चेतावनी प्रणालियों और तटीय सुरक्षा उपायों पर भरोसा करते हुए समुद्र के करीब रहना सुरक्षित समझते हैं। लेकिन केवल भरोसे के दम पर काम नहीं चलता। उदाहरण के लिए डेनमार्क के कई हिस्सों में हो रहा तटीय कटाव दिखाता है कि अब अंदरूनी इलाकों में पहले से योजना बनाना और इन आपदाओं से निपटने की क्षमता को बढ़ाने के उपाय बेहद जरूरी होते जा रहे हैं।

खत्म हो रही एशियाई नदियों की संजीवनी, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन भी प्रभावित



नई दिल्ली)। हिंदुकुश हिमालय (एचकेएच) क्षेत्र की विशाल हिमाच्छादित चोटियां, जो सिंधु से लेकर मेकांग तक एशिया की दस प्रमुख नदियों को पानी देती हैं, अब पहले से कहीं तेजी से सिकुड़ रही हैं। वहीं, हिमालय भले ही सर्दियों में सफेद चमकता है, लेकिन वह चमक अब पहले से बहुत कम समय के लिए रहती है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जम्मू और आईआईटी मंडी के वैज्ञानिकों के नए शोध से पता चला है कि इस क्षेत्र में स्नो ड्राउट यानी असामान्य रूप से कम हिमपात की कमी की घटनाएं अब लगातार बढ़ रही हैं। इसका सीधा असर लगभग 200 करोड़ लोगों की जल सुरक्षा पर पड़ रहा है जो इन नदियों पर निर्भर हैं। इनमें भारत की जीवनदायिनी गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां भी संकट में हैं।

नेचर जर्नल में प्रकाशित शोध हिमालयन स्नो ड्राउट्स डीपेन, थ्रेटनिंग वाटर सीक्यूरिटी फॉर मिलियन्स में पाया गया कि 2015-16 में मध्यम से गंभीर स्नो ड्राउट खासकर अफगानिस्तान और उत्तरी भारत में देखे गए। आईआईटी जम्मू के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के शोधकर्ता हेमंत सिंह के मुताबिक, हमने पाया कि स्नो कवर डेज यानी हिमाच्छादित दिनों में कमी और तेजी से हिम का पिघलना इन सूखों का प्रमुख कारण है। यह मध्य और उच्च हिमालयी क्षेत्र में तापमान वृद्धि का स्पष्ट संकेत है। 1999 से 2016 तक के सैटेलाइट और री-एनालिसिस डेटा का विश्लेषण करते हुए शोधकर्ताओं ने 500 मीटर के पैमाने पर स्नो वॉटर इक्विवैलेंट इंडेक्स (एसडब्ल्यूआई) और हिमाच्छादित दिनों की संख्या (एससीडी) तैयार की। यह अब तक का हिमालयी स्नो ड्राउट का सबसे विस्तृत नक्शा है। शोध के अनुसार, अफगानिस्तान के अमु दरिया, उत्तर-पश्चिमी और ऊपरी सिंधु बेसिन में सबसे ज्यादा स्नो ड्राउट घटनाएं दर्ज हुईं। उत्तर-पश्चिमी बेसिन में अकेले 25 बार तक स्नो ड्राउट दर्ज किया गया। गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसे पारंपरिक रूप से भारी हिमपात वाले बेसिनों में भी पिछले दो दशकों में औसतन 15 दिन तक हिमाच्छादित दिन कम हो गए। नेचर ने आईआईटी जम्मू के सहायक प्रोफेसर दिव्येश वराडे के हवाले से लिखा है, मौसमी हिमक्रीट इन बेसिनों के लिए प्राकृतिक जलाशय का काम करती है। जब यह जलाशय सिकुड़ता है तो कृषि, जलविद्युत उत्पादन और नदी प्रवाह के समय व मात्रा में बदलाव आता है। वसंत ऋतु में हिमगलन पर निर्भर किसान और समुदाय पहले से ही इसका असर महसूस कर रहे हैं। हिंदुकुश हिमालय वैश्विक औसत से तेज गर्म हो रहा है। हालिया अनुमानों के अनुसार 0.74 डिग्री सेल्सियस ज्यादा। शोधकर्ताओं ने पाया कि 3,000 से

6,000 मीटर की ऊंचाई पर स्नो ड्राउट सबसे तीव्र हैं, जहां ऊंचाई-निर्भर वार्मिंग बर्फ को तेजी से पिघला रही है। नेचर ने आईआईटी मंडी के सहायक प्रोफेसर विवेक गुप्ता के हवाले से लिखा, यह ऊंचाई बैंड सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं सबसे ज्यादा हिमसंचय होता है और लंबे समय तक बना रहता है। जब इस क्षेत्र में बर्फ की जगह बारिश होने लगेगी तो पहाड़ों की पूरी जल-प्रणाली बदल जाएगी। अब अधिकांश वर्षा बर्फ के बजाय बारिश के रूप में हो रही है, जिससे तुरंत बहाव बढ़ रहा है और मौसमी बर्फ भंडारण कम हो रहा है। काठमांडू स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (आईसीआईएमओडी) के जलवायु एवं पर्यावरण जोखिम प्रमुख कियांगगोंग झांग कहते हैं, हिमनदों का पीछे हटना एक धीमी रिसाव है, लेकिन स्नो ड्राउट अचानक नल बंद करने जैसा है।

पश्चिमी हिमालय के किसान फसल बोने के समय देर से आने वाले हिमगलन जल पर निर्भर हैं। एक हफ्ते की कमी भी चरम जल आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है। नेचर ने आईसीआईएमओडी के क्रायोस्फियर विशेषज्ञ शेर मुहम्मद के हवाले से लिखा, सिंधु बेसिन में कुल बहाव का लगभग 40 फीसदी और हेलमंद बेसिन में 70 फीसदी से ज्यादा मौसमी हिमगलन से आता है यानी हिमनदों से सात गुना ज्यादा। शोध में अमु दरिया, सिंधु, मेकांग और साल्विन बेसिन को सबसे ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्र बताया गया है। ऊपरी सिंधु में 2002 से 2018 के बीच हिमाच्छादित दिन औसतन 12 कम हुए। नेचर ने लिखा है, झांग बताते हैं कि 2018 के बाद भी एमओडीआईएस सैटेलाइट डेटा से रिकॉर्ड कम हिमाच्छादन दिख रहा है। बार-बार विफलता अब स्पष्ट ट्रेंड बन चुकी है। शोधकर्ता कहते हैं कि नीति-निर्माताओं को केवल हिमनद-केंद्रित दृष्टिकोण छोड़कर पूरे पर्वतीय जल चक्र को देखना होगा। हेमंत सिंह कहते हैं, हिम को रणनीतिक जल संपत्ति की तरह देखना होगा। इसका नक्शा बनाना, संरक्षण करना और हिमगलन जल का कुशल प्रबंधन करना होगा। नेचर जर्नल में झांग और मुहम्मद के हवाले से कहा गया है कि जलविद्युत और सिंचाई योजनाकारों को मौसम पूर्वानुमान की तरह ही हिम की जानकारी का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही हिमनद, मौसमी हिम, परमाफ्रॉस्ट, झरने और भूजल डू पूरे क्रायोस्फियर-जल तंत्र को एकीकृत कर अनुकूलन रणनीति बनानी होगी। परमाफ्रॉस्ट पिघलने और झरने सूखने से पहाड़ी सड़कें और नहरें पहले से ही क्षतिग्रस्त हो रही हैं। यदि गर्मी इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले दशकों में हिमालय का एशिया का जल मीनार वाला दर्जा गंभीर खतरे में पड़ जाएगा। मॉडल बता रहे हैं कि मध्य ऊंचाई पर बर्फ कम समय तक रहेगी और अधिक वर्षा बारिश के रूप में होगी। कुछ बेसिनों में स्नो ड्राउट लगभग हर साल होने की आशंका है। गुप्ता के मुताबिक, हर गायब हिमाच्छादित दिन का मतलब एक दिन कम संग्रहीत जल है। - संकलन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय बस स्टैंड पर रिक्शा संचालकों और बस यात्रियों से की चर्चा

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को उज्जैन में नानाखेड़ा के पं. दीनदयाल उपाध्याय बस स्टैंड पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बस स्टैंड से अंतरराज्यीय बसें संचालित की जाती हैं। साथ ही राज्य के विभिन्न शहरों में आवागमन के लिए भी यहां से बसें संचालित होती हैं। मुख्यमंत्री ने यहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और यात्रियों, ऑटो रिक्शा संचालकों से चर्चा भी की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बस स्टैंड पर बस यात्रियों और स्थानीय दुकानदारों से चर्चा की। उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही एक चाय की दुकान पर चाय भी बनाई और नागरिकों से चाय पर चर्चा की। मुख्यमंत्री के सादगीपूर्ण व्यवहार की नानाखेड़ा बस स्टैंड के स्थानीय लोगों ने प्रशंसा की। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री गौतम टेटवाल एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।



भाषा और संस्कृति एक-दूसरे के हैं पूरक – मुख्यमंत्री डॉ. यादव

हिन्दी लोकभाषा हमारे माथे की है बिन्दी साहित्य का एक ही रंग- राग और आनंद

हमने सदैव अधिसत्ता नहीं, प्रभुसत्ता की भावना रखी



भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भाषा और संस्कृति एक-दूसरे की सहज पूरक हैं। संस्कृति, भाषा को वह कथा-बीज देती है, जिनसे लोक-साहित्य से लेकर वैश्विक साहित्य जन्म लेता है और भाषा, संस्कृति को वह अभिव्यक्ति देती है, जिससे परंपराएं पीढ़ियों तक सुरक्षित यात्रा कर पाती हैं। भाषा और संस्कृति दोनों एक-दूसरे की संरक्षक भी हैं। साहित्य का एक ही रंग होता है, राग और आनंद का। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हिन्दी भाषा सच्चे अर्थों में लोक भाषा है। हिन्दी हमारे माथे की बिन्दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज हमारी हिन्दी वैश्विक मंच पर भारत की पहचान बन रही है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति ने अधिसत्ता नहीं, सदैव प्रभुसत्ता और लोक बंधुत्व की भावना रखी। हमारी संस्कृति जियो और जीने दो की पवित्र भावना से ओत-प्रोत है। यही कारण है कि आज भारतीय संस्कृति दुनियाभर में अपनी अलग पहचान रखती है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को रवीन्द्र भवन में साहित्य और कला के सबसे बड़े उत्सव 'विश्वरंगडू2025' टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव में देश-विदेश से आए साहित्यकारों, कलाकारों और युवाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी का मध्यप्रदेश की धरती पर स्वागत-अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की सृजनात्मक और कलात्मक धरती हिन्दी भाषा और भारतीय संस्कृति को जोड़ने वाली सेतु बन गई है। हमारा भोपाल अब भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा चेतना और वैश्विक साहित्यिक संवाद का केन्द्र बन गया है। महोत्सव में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में कई सत्र, कविता पाठ, पैनल चर्चा, कला प्रदर्शनियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जा रही हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव को विश्वरंग का कैटलॉग, हिन्दी भाषा की मार्गदर्शिका एवं पुस्तकें भेंट की गईं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि साहित्य सच्चे अर्थों में एक दीर्घ साधना है और साहित्यकार एक प्रयोगधर्मी साधक है। साहित्यकार अपनी

कल्पनाशीलता, चिंतन और रचनात्मकता से ऐसे शब्द गढ़ता है, जो कालांतर में अमर हो जाते हैं। उन्होंने साहित्य और कला को समाज का दर्पण बताते हुए कहा कि विश्वरंग जैसे आयोजन नई पीढ़ी में सृजनशीलता और संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रवीन्द्रनाथ टैगोर की विचारधारा और उनकी वैश्विक दृष्टि आज भी दुनिया भर में संवाद, सौहार्द और मानवता का संदेश देती है। विश्वरंगडू2025 जैसा मंच साहित्य, कला, संगीत और संस्कृति को जोड़ने का माध्यम है। यह आयोजन हमारी समृद्ध देशज कला एवं संस्कृति का पोषक है। यह हमारे साहित्यिक वैविध्य में भी एकात्मकता का संदेश देता है। साहित्य लोक-समाज को दिशा देने वाले कर्म के साथ हमारी जीवनधारा का मानस मर्म भी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि दुनिया में कई देशों की अपनी-अपनी संस्कृति है। लेकिन भारत का उद्भव मातृ सत्ता के आधार पर विश्व बंधुत्व को लेकर आगे बढ़ने की रही है। ब्रिटिश काल से ही भारतवंशी दुनिया के अनेक देशों में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। भारतीय इतिहास पर नजर डालें, तो अंग्रेज कभी एग्रीमेंट कर भारतीयों को कृषि और पशुपालन सहित अन्य कार्यों के लिए अपने स्वामित्व वाले देशों में ले गए थे। इन्हीं को गिरमिटिया कहा गया है। तब अंग्रेजों ने देशभर से इन शुभ कार्यों के लिए सुयोग्य लोगों को चुना था। आज विश्वरंग के माध्यम से 70 देशों के साहित्यकार, कलाकार और संस्कृति संरक्षक भोपाल आए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोविड के कठिन दौर में भारत ने जियो और जीने दो के भाव के आधार पर बंधुत्व का संदेश दिया। अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों तक दवाएं और मेडिसिन

भेजी गईं, जिसके बाद ऐसे भी दृश्य सामने आए जब एक देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को धन्यवाद देते हुए उनके चरण भी स्पर्श किये। हमारा यह उदार भाव ही भारतवंशियों को गौरव का अनुभव कराता है। कुछ काम बोलकर नहीं होते, उन्हें करके ही दिखाना पड़ता है।

सात साल में सत्तर देशों तक पहुंचा विश्वरंग

विश्वरंग फाउंडेशन के संस्थापक और रवीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉ. संतोष चौबे ने कहा कि विश्वरंग एक ऐसा आयोजन है, जिसकी शुरुआत मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से हुई। विश्वरंग के पहले आयोजन 2019 में केवल 16 देश शामिल थे, अब इसमें 70 से अधिक देश सहभागिता कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह सातवां आयोजन है। विश्वरंग में 40 देशों के 70 से अधिक साहित्यकार एवं पत्रकार सहभागिता कर रहे हैं। आयोजन में 1000 से अधिक अतिथि आए हैं। विश्वरंग में 100 से अधिक हिंदी पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा। आयोजन में श्रीकृष्ण लीला मंचन भी आकर्षण का केंद्र है। यह आयोजन युवाओं के लिए कौशल विकास एवं रोजगार प्राप्त करने में भी सहभागी बन रहा है। विश्वरंग में समाचार-पत्र, कला-संस्कृति एवं विज्ञान आधारित 7 अलग-अलग प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। दुनिया के कई देशों में हिंदी को आगे बढ़ाने वाले साहित्यकार भारत आना चाहते हैं और सरकार के साथ मिलकर हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वर्ष 2019 से 2024 तक, विश्वविद्यालय ने विश्वरंग के 6 भव्य और अविस्मरणीय आयोजन किए जो न केवल मध्यप्रदेश, बल्कि पूरे विश्व में हिन्दी प्रेमियों को जोड़ने का अद्भुत प्रयास रहे हैं। विश्वरंग में 80 से अधिक सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी ओलंपियाड में 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया है। उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि विश्वरंग फाउंडेशन को अब सरकार का साथ मिल रहा है और अब मध्यप्रदेश सरकार इस विशिष्ट महोत्सव को शासन की ओर से आयोजित करने की ओर कदम बढ़ा रही है। कार्यक्रम में हिन्दी सेवी डॉ. सिद्धांत चतुर्वेदी, डॉ. अदिति चतुर्वेदी, डॉ. अरुण जोशी, श्री राहुल कोठारी एवं अतिथि सहित विद्वतजन, दुनियाभर से आए रचनाकार, साहित्यकार, भाषाविद्, हिन्दी प्रेमी, साहित्य प्रेमी और कलाप्रेमी उपस्थित थे।

साइक्लोन दित्वा ने श्रीलंका में मचाई तबाही, बाढ़-लैंडस्लाइड से 123 से ज्यादा मौते



कोलंबो । श्रीलंका इस समय एक बड़े मानवीय संकट से गुजर रहा है। साइक्लोन दित्वा ने देश में ऐसी तबाही मचाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बारिश से निचले इलाके डूब गए और जगह-जगह लैंडस्लाइड शुरू हो गए। सबसे दुखद बात यह है कि 123 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 130 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। करीब 3.7 लाख लोग प्रभावित हैं और 195 राहत शिविरों में 14,000 लोग रह रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मातले में तो सिर्फ 24 घंटों में 540 मिमी बारिश हुई। यह बारिश सामान्य सीमा से कई गुना ज्यादा है। पिछले 10 दिनों में करीब 1000 मिमी बारिश ने पूरे इलाकों को तबाह कर दिया। वैज्ञानिकों का कहना है कि 150 मिमी बारिश भी लैंडस्लाइड करा सकती है, और यहां तो 500 मिमी से ज्यादा पानी बरस चुका है। सबसे ज्यादा चिंता कोलंबो और गंपाहा की है, जहां केलानी और अट्टानगालु नदियां खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी हैं। लोगों को सुरक्षित जगह जाने और जरूरी कागजात संभालकर रखने को कहा है। तूफान ने श्रीलंका के बुनियादी ढांचे को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। तीन बड़े पुल- मोरगहकंडा मेन ब्रिज, एलाहेरा ब्रिज और कुमारा एला ब्रिज पूरी तरह बह गए। बिजली की लाइनें टूटने से देश के 25-30 फीसदी हिस्से में बिजली की आपूर्ति नहीं की जा रही है। ट्रेनें रद्द हैं और कई परीक्षाएं टाल दी गई हैं। श्रीलंका राष्ट्रपति ने आपातकालीन कानून लागू किया और बिजली, प्यूल, अस्पताल और पानी को जरूरी सेवाएं घोषित किया है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम को राहत केंद्र बनाया गया है, जहां 3,000 लोगों को ठहराया जा सकता है। भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ भारत ने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया और ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। भारतीय नौसेना के विक्रांत और उदयगिरि जहाज राहत सामग्री लेकर श्रीलंका पहुंचे। इनमें 4.5 टन सूखा राशन, 2 टन ताजा खाने का सामान और अन्य जरूरी सामग्री शामिल है। विशेषज्ञों ने इसे अभूतपूर्व स्थिति बताया है और कहा है कि आने वाले दो दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं। तूफान अभी भी त्रिंकोमाली के पास है और भारी बारिश का दौर जारी है।

जमीन-मिट्टी-पानी सीमित, भुखमरी से बचने के लिए दिखानी होगी समझदारी-एफएओ

न्यूयार्क । संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने अपनी नई प्रमुख रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि 2050 तक 10 अरब लोगों को भोजन खिलाने के लिए हमें भूमि, मिट्टी और पानी का बहुत समझदारी से उपयोग करना होगा। भविष्य की खाद्य सुरक्षा तभी संभव है जब हम इन संसाधनों का सही और जिम्मेदारी से प्रबंधन करें। एक दिसंबर को जारी द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर 2025 की नवीनतम रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी महत्वपूर्ण संसाधन सीमित हैं। इन्हें सुरक्षित रखना न केवल वर्तमान बल्कि आने वाले दशकों में भी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहद आवश्यक है। अधिक और बेहतर उत्पादन की क्षमता विषय के तहत रिपोर्ट में कहा गया है कि भूमि और जल संसाधनों में भोजन उत्पादन को टिकाऊ रूप से बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें अब तक अनदेखा किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में लगभग 67.3 करोड़ लोग भूख का सामना कर रहे थे, कई इलाके अभी भी बार-बार होने वाली गंभीर खाद्य समस्याओं से परेशान हैं। जैसे-जैसे वैश्विक जनसंख्या 2050 तक 9.7 अरब के करीब पहुंचेगी, इन समस्याओं में और वृद्धि होगी। ऐसी स्थिति में कृषि क्षेत्र को 2012 की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक भोजन, चारा और रेशा, और साथ ही 25 प्रतिशत अधिक मीठा पानी उपलब्ध कराना होगा। पिछले 60 वर्षों में वैश्विक कृषि उत्पादन तीन गुना हो गया, जबकि कृषि भूमि में मात्र 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन इसका पर्यावरण और समाज पर भारी प्रभाव पड़ा। एफएओ के आंकड़ों के अनुसार, इंसानों की गतिविधियों के कारण जो भी जमीन खराब हो रही है, उसमें से 60 प्रतिशत हिस्सा कृषि भूमि का है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र का विस्तार अब संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, वनों की कटाई या नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों को कृषि में बदलना उन महत्वपूर्ण जैव-विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को नष्ट करेगा, जिन पर कृषि स्वयं निर्भर करती है।